बवाना मॉडल से यूपी के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की बदलेगी सूरत

जल निकासी से लेकर कचरा प्रबंधन तक का होगा अध्ययन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में जलभराव, दूषित पानी और ठोस कचरे के निस्तारण की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के मॉडल को अपनाने की तैयारी है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बुधवार को बवाना औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण कर सड़क, जल निकासी, सीवेज ट्रीटमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन, ट्रकों की पार्किंग, वाहनों और श्रमिकों के प्रबंधन सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

मंत्री ने देखा कि बवाना में औद्योगिक गतिविधियों के साथ बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरणीय प्रबंधन को किस तरह जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य यूपी के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ पर्यावरणीय समस्याओं का स्थायी समाधान तलाशना है। बवाना औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 2011 में विकसित हुआ है और यहां 15 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। इसे एशिया के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां उत्तर भारत का बड़ा एसटीपी प्लांट पीपीपी मॉडल पर संचालित है। नंदी ने औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक और प्रदूषित पानी के उपचार के लिए स्थापित साझा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (सीईटीपी) का भी निरीक्षण किया।

यूपी में वर्ष 2000 से पहले विकसित कई औद्योगिक क्षेत्रों में समय के साथ जलभराव, दूषित जल और ठोस कचरे की समस्याएं बढ़ी हैं। बवाना की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर इनके लिए उपयोगी मॉडल तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

नंदी ने दिल्ली सरकार की एजेंसी डीएसआईआईडीसी और बवाना इन्फ्रा के अधिकारियों के साथ बैठक कर संयंत्रों के संचालन और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान वन महोत्सव के तहत पौधारोपण भी किया गया। ब्यूरो